



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2007/आषाढ़ 15, 1929

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2007/ASADHA 15, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2007

**विषय :** चीन से रबड़ रसायनों अर्थात् एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई तथा टीएमटी एवं चीन तथा कोरिया जन. गण. से पी एक्स-13 (6 पीपीडी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/5/2007-डीजीएडी.—यतः मैसर्स आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसरण में चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायनों अर्थात् एमबीटी, सीबीएस, टीक्यूडी, पीवीआई तथा टीएमटी (जिन्हें एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) तथा चीन व कोरिया जन. गण., जिन्हें (एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पी एक्स 13 (पीपीडी) (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है और सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने एवं ऐसी पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, अतः कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने हेतु और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने हेतु, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने की दृष्टि से पर्याप्त होगी, उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में कथित पाटन एवं इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ।

## 2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद रबड़ रसायन है, अर्थात् :—

- एमबीटी जिसका रासायनिक वर्णन 2-मरकेप्टो बेंजोथाइजोल है और इसके अन्य व्यापारिक/ब्रांड नाम एक्सलरेटर एम, एक्सलरेटर एमबीटी आदि हैं ।

- (ii) सीबीएस जिसका रासायनिक वर्णन एन- साइक्लोहेक्सिल 2- डीजोथाइजोल सल्फेनामाइड है, के अन्य व्यापारिक/ब्रांड नाम एक्सलरेटर सीजेड, एक्सलरेटर एनजेए, सीबीएस आदि हैं।
- (iii) टीडीक्यू जिसका रासायनिक वर्णन डीमिथाइल 2, 2, 4- ट्राइफेनिल- 1, 2- डीहाइड्रोक्विनोलीन है, के अन्य व्यापारिक/ब्रांड नाम टीएमआर या एटीआक्सिडेंट आदि हैं।
- (iv) पीवीआई जिसका रासायनिक वर्णन एन (साइक्लोहेक्सिल थियो) थेलिमाइड है, के अन्य व्यापारिक/ब्रांड नाम एंटी स्कॉच एजेंट सीटीपी पीवीआई आदि हैं।
- (v) टीएमटी जिसका रासायनिक वर्णन टेट्रा मिथाइलथियुरम डिस्फोफाइट है के अन्य व्यापारिक/ब्रांड नाम एक्सलरेटर टीएमटीडी, थिरुम सी आदि हैं।
- (vi) पीएक्स- 13 (6 पीपीडी) जिसका रासायनिक वर्णन एन 1, 3 डिमिथाइल ब्यूटाइल- एन फिनाइल-पी-1 है, के अन्य व्यापारिक/ब्रांड नाम 6 सी, पीएमएस 13, सिरनटोक्स 4020, एंटी आक्सीडेंट 4020, कुम्होरेक्स 13 बल्केनोक्स 4020 आदि हैं।

प्रयोक्ता उद्योग मोटे तौर पर दो वर्गों में बंटे हुए हैं टायर गार्डर- टायर। दोनों वर्गों में इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के खड़ों- प्राकृतिक और सिंथेटिक के प्रसंस्करण से किया जाता है। इसे किसी उद्योग के लिए प्रमुख निविद्धि/कच्ची सामग्री नहीं बताया गया है और यह बस एक प्रसंस्करण रसायन है।

संबद्ध खड़ रसायन जिसकी उल्लेख बताया गया है का प्रयोग प्राकृतिक खड़ और कृत्रिम खड़ आधारित यौगिकों के उपचार में किया जाता है। इस उत्पाद का उद्योगीय स्तर पर भी कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आयातित बताया गया है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण कौशल सम्पन्न हैं और जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। चूंकि इन उत्पादों का कोई समर्थन वर्गीकरण नहीं है इसलिए ऑकडा संकलन एजेंसियों (आईबीआईएस) द्वारा प्रदत्त सूचना का प्रयोग किया गया है।

### 3. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

याचिकाकर्ता अर्थात् मै. नेशनल ऑर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक अर्थात् मै. इनसेस इंडिया प्रा. लि., अथवा पीएमसी खड़ कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि., हुगली एण्ड मरकैम लि., एनीकुलम हैं। तथापि, उपर्युक्त तीनों कंपनियों द्वारा उत्पादन में कटौती करने की बात कही गई है और ये आयात कर रहे हैं। याचिकाकर्ता कुछ कंपनियों से जॉब वर्क आधार पर उत्पादन कार्यकलापों के कुछ हिस्से को सम्पन्न कराते हैं, जो यह कार्य केवल याचिकाकर्ता के लिए करती हैं। याचिकाकर्ता को इन कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता कंपनी के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता नियमावली के अन्तर्गत सम्यक्ता संबंधी शर्तों को पूरा करता है और नियमावली के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता "घरेलू उद्योग" के अन्वयेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से सम्यक्ता जांच हेतु वर्तमान याचिका दायर करने की स्थिति में है।

#### 4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, वस्तुओं की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं से तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इनकी विशेषताएं मिलती-जुलती हैं। आगे यह भी दावा किया गया है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित समान वस्तु माना जा रहा है।

#### 5. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू तथा बीबीआई, टीएमटी एवं पीएक्स-13 (6 पीपीडी) के लिए चीन जन.गण. अथवा संबद्ध देश तथा उत्पाद पीएक्स-13 (6 पीपीडी) के लिए कोरिया जनवादी गणराज्य अथवा संबद्ध देश है।

#### 6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जन.गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। अतः याचिकाकर्ता ने उत्पादन की परिकल्पित लागत तथा यूरोप की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। कोरिया जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के अनुमानों पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि तीसरे देशों की कीमतों अथवा लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक देशों में वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है और इस संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने भारत में यथासमायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

#### 7. निर्यात कीमत

यह देखते हुए कि उत्पाद का कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है, निर्यात कीमत का निर्धारण आईबीआईएस द्वारा संकलित सौदेवार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना द्वारा निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण सीआईएफ कीमत एवं भाड़े, ऋण लागत, बैंक प्रभारों, अंतर्देशीय भाड़े, बीमा एवं कमीशन इत्यादि में कीमत समायोजन के विभिन्न तत्वों को अपना कर किया गया है।

## 8. पाटन मार्जिन

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

## 9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ताओं ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप आयात में समग्र रूप से और वृद्धि और भारत में उत्पादन एवं खपत से सामेक्ष हुई वृद्धि अत्यधिक कीमत कटौती, जर्मन एवं कोरिया गंगराज्य के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी और धरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी, इसका जुगाई गई पूंजी से आय, नकद लाभ आदि में वर्ष 2005-06 तक रुझान होने के पश्चात आती निर्यात के बारे में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं को हो रही वास्तविक क्षति का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इसके अलावा, वास्तविक क्षति के अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि आयातों में वृद्धि की दर अत्यधिक कीमत कटौती और निर्यात प्रयुक्त क्षमताओं के आधार पर पाटित आयातों से वास्तविक क्षति का स्वतंत्र उत्पन्न हो रहा है।

## 10. जांच अवधि (पीओआई) :

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2006 से मार्च, 2007 तक है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2003 - मार्च, 2004; अप्रैल 2004 - मार्च 2005; अप्रैल 2005 - मार्च, 2006 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होंगी।

## 11. सूचना प्रस्तुत करना:

संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में स्थित उनके दलालों को चाहिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा धरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचना दी गई है ताकि वे विनिर्दिष्ट ढंग एवं विधि से सभी संगत सूचनाएं दाखिल कर सकें। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्न पते पर लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।

## 12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें उक्त सूचना, उन्हें लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज करेंगे।

## 13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में सूचना का संक्षिप्तिकरण सम्भव नहीं है, तो उसके कारणों का विवरण प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

## 14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्ष उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है, अथवा उचित समय के भीतर इसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2007

**Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning the imports of Rubber Chemicals viz., MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT from China and PX-13 (6PPD) from China and Korea RP.**

**No. 14/5/2007-DGAD.**—Whereas M/s. National Organic Chemical Industries Limited have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), alleging dumping of Rubber chemicals viz., MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported

from China (hereinafter referred to as the subject country) and PX-13 (PPD) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), and have therefore requested for initiation of an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject countries and levy anti-dumping duty on the such dumped subject goods.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

## 2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The products under consideration in the present petition are Rubber Chemicals viz.

- i) MBT, having chemical description 2-Mercapto Benzothiazole with other trade / brand names as Accelerator M, Accelerator MBT etc.
- ii) CBS, having chemical description N-cyclohexyl-2-Benzothiazole Sulphenamide with other trade name/brand names as Accelerator CZ, Accelerator HBS, CBS etc.
- iii) TDQ, having chemical description Polymerized 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline with other trade/brand names as TMR or Antioxidant RD etc.
- iv) PVI, having chemical description N-(Cyclohexylthio)Phthalimide with other trade /brand names as Anti Scorch agent CTP, PVI etc.
- v) TMT having chemical description Tetramethylthiuram Disulfide with other trade/brand names as Accelerator TMTD, Thiuram C etc.
- vi) Px-13 (6PPD) having chemical description N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-P-1 with other trade/brand names as 6C, Pilflex 13, Sirantox 4020 Antioxidant 4020, Kumhonax 13 Vulcanox 4020 etc.

The user industry is broadly divided into two segments- tyre and non-tyres. In both the segments, it is used for processing of various types of rebbers-natural and synthetic. It is stated to be not a principal input / raw material / to any industry and is only a processing chemical.

The subject rubber chemicals as detailed above are used in treating natural rubber and synthetic rubber based compounds. The product does not have a dedicated classification even at 8 digit level. The product is stated to be imported under chapter 29 and 38 of the Customs Tariff Act. However Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of

investigation. Since the products do not have a dedicated classification, information provided by the data compiling agencies ( IBIS ) has been used

### 3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Apart from the petitioner i.e. M/s. National Organic Chemical Industries Limited, there are three other producers of the subject goods in India viz. M/s. Lanxess India Pvt. Ltd., Thane, PMC Rubber Chemicals India Pvt. Ltd., Hoogly and Merchem Ltd., Ernakulam. The three companies as above are however stated to have reduced their production and are resorting to import. Petitioner is getting some part of production activity done on job work basis from some companies who are stated to be doing this exclusively for the petitioner. The petitioner has support from these companies. The production by Petitioner Company constitutes a major proportion in the Indian production. The petition satisfies the condition of standing under the Rules and the petitioner constitutes "domestic industry" within the meaning of the Rules. The applicant has the standing to file the present petition for anti-dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3) (a) of Anti-Dumping Rules.

### 4. LIKE ARTICLE

Petitioner has claimed that there is no significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to ones imported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. For the purpose of present investigation, product under consideration produced by the petitioner are being treated as like article to ones imported from the subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

### 5. COUNTRIES INVOLVED

The country involved in the present investigations are China PR or subject country for products MBT, CBS, TDQ, and PVI, TMT & Px-13 (6PPD) and Korea RP or subject country for product PX-13(6PPD).

### 6. NORMAL VALUE

The petitioners have claimed that China is a non-market economy. The petitioners have therefore, claimed determination of normal value on the basis of constructed cost of production and also based upon price in Europe. In respect of Korea RP normal value is based on estimates of cost of production. Petitioners have claimed that normal value cannot be determined on the basis of

price or costs in third countries for the reason that the goods are not produced in several countries and no information is publicly available in this regard. Petitioners have determined normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

## 7. EXPORT PRICE

The export price has been determined based on the transaction wise data compiled by IBIS, considering that the product does not have dedicated classification. Net export price has also been determined from the CIF price and adopting various elements of price adjustments towards freight, credit cost, bank charges, inland freight, insurance and commission etc to arrive at ex-works export price.

## 8. DUMPING MARGIN

There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

## 9. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioners have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping in terms of increase in imports in absolute terms and relative to production & consumption in India, significant price undercutting, increase in market share of China & Korea RP and decline in the market share of the domestic industry, deterioration in profits, return on capital employed, cash profits after improvements up to 2005-06, etc. There is sufficient prima-facie evidence of material injury being suffered by the petitioners caused by dumped imports from subject countries. Further, in addition to material injury, petitioners have claimed that the imports are causing threat of material injury from the dumped imports based on rate of increase in imports, significant price undercutting and significant unutilized capacities.

## 10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI):

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is April 2006-March 2007. The injury investigation period will however, cover the period April, 2003-March, 04; April, 2004-March, 05; April, 2005-March, 06 and period of investigation.



## 11. SUBMISSION OF INFORMATION:

The exporters in the subject countries and their Government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce,  
Room No. 240, Udyog Bhavan,  
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

## 12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

## 13. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

## 14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

3052 GI/07-3